

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीड मॉडल

### प्रलिस के लिये:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीड मॉडल

### मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों के लिये महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के 'बीड मॉडल' के राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिये कहा।

## प्रमुख बिंदु:

### बीड मॉडल:

- बीड महाराष्ट्र का एक जिला है जो सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित है।
- **80-110 फॉर्मूला:** इस मॉडल को 80-110 फॉर्मूला भी कहा जाता है।
  - बीमा फर्म को सकल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक के दावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बीमाकर्ता को नुकसान (पुल राशि) से बचाने के लिये एकत्र किये गए प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक मुआवजे की लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
  - हालाँकि यदि मुआवजा एकत्र किये गए प्रीमियम से कम है तो बीमा कंपनी राशि का 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में रखेगी और शेष राशि राज्य सरकार (प्रीमियम अधिशेष) को प्रतपूर्त करेगी।

### इस मॉडल को लागू करने का कारण:

- **राज्यों को लाभ:**
  - **फंड का एक अन्य स्रोत:** अधिकांश वर्षों में क्लेम-टू-प्रीमियम अनुपात कम होता है। बीड मॉडल में बीमा कंपनी के लाभ में कमी आने की उम्मीद है और राज्य सरकार को धन के दूसरे स्रोत तक पहुँच प्राप्त होगी।
  - **PMFBY के वित्तपोषण बोझ को कम करना:** प्रतपूर्तकी गई राशि से अगले वर्ष के लिये राज्य द्वारा PMFBY हेतु कम बजटीय प्रावधान हो सकता है, या एक वर्ष के फसल के नुकसान के मामले में राशि का भुगतान करने में मदद मिल सकती है।
- **PMFBY में खामियाँ:**
  - वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्यों ने PMFBY हेतु प्रीमियम बलि जमा करने के लिये वर्षों से असहमत जताई है, जिसके परिणामस्वरूप बीमाकर्ता समय पर किसानों के दावों का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
  - वर्ष 2020 में मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले में सामान्य से कम मानसून की वर्षा ने बीमाकर्ताओं को खरीफ 2020 हेतु PMFBY के तहत जिले के किसानों को कवर करने से रोक दिया।

### चुनौतियाँ:

- इस पर सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार अतिरिक्त राशि कैसे जुटाएगी और प्रतपूर्तकी गई राशि को कैसे प्रशासित किया जाएगा।
- किसानों को इस मॉडल का कोई सीधा लाभ होता नहीं दिख रहा है।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।

- यह फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।
- **दायरा:** सभी खादय और तलिहन फसलें तथा वार्षिक वाणजियकि/बागवानी फसलें जिनके लिये पछिली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
- **प्रीमियम:** सभी खरीफ फसलों के लिये किसानों द्वारा नरिधारति प्रीमियम का भुगतान 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणजियकि और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम 5% है।
  - किसानों के हस्से से अधिक प्रीमियम लागत पर राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सडी दी जाती है।
  - हालाँकि भारत सरकार इस कषेत्तर को बढ़ावा देने के लिये पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रीमियम सब्सडी का 90% साझा करती है।
- **PMFBY 2.0 (PMFBY को वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न में नया रूप दिया गया था):**
  - **पूरी तरह से स्वैच्छकिक:** वर्ष 2020 से पहले यह योजना उन किसानों के लिये वैकल्पिक थी, जिनके पास ऋण लंबति नहीं था लेकिन ऋणी किसानों हेतु यह अनविर्य था। वर्ष 2020 से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है।
  - **केंद्रीय सब्सडी की सीमा:** कैबिनेट ने इस योजना के तहत असचिति कषेत्तरों/फसलों के लिये 30% और सचिति कषेत्तरों/फसलों हेतु 25% तक की प्रीमियम दरों के लिये केंद्र की प्रीमियम सब्सडी को सीमति करने का नरिणय लया।
  - **राज्यों को अधिक लचीलापन:** सरकार ने राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों को PMFBY को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतरिकित जोखमि कवर/सुवधियों का चयन करने का वकिल्प दिया है।
  - **IEC गतविधियों में नविश:** बीमा कंपनियों को सूचना, शकिषा और संचार (IEC) गतविधियों पर एकत्तरति कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना पड़ता है।

### PMFBY के तहत प्रोद्योगिकी का उपयोग:

- **फसल बीमा एप:**
  - यह किसानों को आसान नामांकन सुवधि प्रदान करता है।
  - किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की सूचना देना आसान बनाना।
- **नवीनतम तकनीकी उपकरण:** फसल के नुकसान का आकलन करने के लिये उपग्रह इमेजरी, रमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्त्रमि बुद्धमित्ता और मशीन लर्नगि का उपयोग कया जाता है।
- **PMFBY पोर्टल:** भूमि अभलिखों के एकीकरण हेतु।

### योजना का प्रदर्शन:

- इस योजना में प्रतविर्य के अनुसार औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन शामिल हैं।
- आधार सीडगि (इंटरनेट बैंकगि पोर्टल के माध्यम से आधार को लकि करना) ने किसानों के खातों में सीधे दावा नपिटान में तेज़ी लाने में मदद की है।
- एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है किराजस्थान में वर्ष 2019-20 में रबी सीज़न के दौरान टडिडियों के हमले के कारण लगभग 30 करोड़ रुपए के मध्य-मौसम प्रतकिलता के दावे कयि गए हैं।

### स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस